



प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहरादून : दिनांक : ) / जनवरी, 2019

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या मान्यता/केयू/सम्बद्धता/146 दिनांक 13.06.2018 व पत्र संख्या मान्यता/सम्बद्धता/के०यू०/490 दिनांक 04.01.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व कुलपति जी की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अधीन निम्न संस्थान को निम्नांकित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में वर्णित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :-

क्र०सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
1	2	3	4	5
1	रुद्रपुर कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्राम भगवानपुर रुद्रपुर उधमसिंहनगर	1-बी०एससी० (पी०सी०एम०) 2-बी०कॉम० (आनर्स) 3-बी०एच०एम० 4-बी०एससी० (एक्यूरियल साइन्स) 5-बी०एससी० (फायर एण्ड सेफ्टी)	60 सीट 60 सीट 60 सीट 60 सीट 60 सीट	सत्र 2018-19 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता।

- संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत कुलपति का यह दायित्व होगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासनादेशों व इस सचिवालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधारभूत सुविधा व निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा० कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।
- संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

